भारत में एपल की रिकॉर्ड कमाई

- सीईओ जॉन टर्नस ने बताया देश बना ग्रोथ इंजन
- मार्जिन घटने की आशंका से शेयर 4% टूटे

आईफोन की मांग ऑलटाइम हाई



नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 नवंबर. भारत में आईफोन की बढ़ती मांग ने अमेरिकी टेक कंपनी एपल को सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड कमाई दिलाई है. कंपनी के सीईओ जॉन टर्नस ने बताया कि भारत में आईफोन और मैक की मांग अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है. टर्नस ने सीईओ बनने के बाद पहली बार तिमाही नतीजों की जानकारी दी.

हालांकि, उन्होंने भारत से हुई कमाई का अलग आंकड़ा नहीं बताया. उनके मुताबिक, भारतीय बाजार कंपनी के वैश्विक कारोबार के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि केंद्र बनकर उभरा है. एपल का सितंबर तिमाही में वैश्विक राजस्व 114.5 अरब डॉलर यानी करीब 10.80 लाख करोड़ रुपए रहा. पिछले साल की समान तिमाही में यह 102.5 अरब डॉलर था. इस तरह कंपनी की कमाई में करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई. पूरे साल का राजस्व भी 416 अरब डॉलर से बढ़कर रिकॉर्ड 479 अरब डॉलर पहुंच गया. कंपनी की कुल कमाई में आईफोन की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही. सितंबर तिमाही में आईफोन से 57.6 अरब डॉलर का राजस्व मिला, जो कुल आय का 50.3 प्रतिशत है. सर्विसेज कारोबार से 31.6 अरब डॉलर, मैक से 10.8 अरब डॉलर, वियरेबल से 8.3 अरब डॉलर और आईपैड से 6.2 अरब डॉलर की कमाई हुई. भारत में पुराने आईफोन को नए मॉडल से अपग्रेड करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. नो-कॉस्ट ईएमआई, आसान कर्ज सुविधा, पुराने फोन की बेहतर एक्सचेंज वैल्यू और छोटे शहरों तक स्टोर व रीसेलर नेटवर्क का विस्तार भी बिक्री बढ़ाने में मददगार रहे.

रिकॉर्ड कमाई के बाद भी शेयर गिरे

कंपनी की मजबूत कमाई के बावजूद निवेशकों की चिंता बढ़ी है. मेमोरी चिप की कीमतों में बढ़ोतरी और एआई आधारित सिरी के विकास पर खर्च के कारण दिसंबर तिमाही में ग्रॉस मार्जिन घटकर 45 से 46 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सितंबर तिमाही में यह 47.9 प्रतिशत था. इसी आशंका के चलते प्री-मार्केट कारोबार में एपल के शेयर करीब 4 प्रतिशत तक गिर गए.

सेवा क्षेत्र की रफ्तार 4 महीने में सबसे तेज

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 नवंबर. घरेलू मांग में मजबूती और नए ऑर्डरों की बढ़ती संख्या ने देश के सेवा क्षेत्र को नई रफ्तार दी है. अक्टूबर में सेवा क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियां पिछले चार महीनों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं. एचएसबीसी के ताजा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के मुताबिक, सेवा क्षेत्र का सूचकांक सितंबर के 55.2 से बढ़कर अक्टूबर में 55.8 पर पहुंच गया. यह लगातार विस्तार और कारोबारी परिस्थितियों में सुधार का संकेत है.

सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों को मिलाकर तैयार किया जाने वाला संयुक्त पीएमआई भी अक्टूबर में बढ़ा है. सितंबर में यह 55.9 था, जो अक्टूबर में बढ़कर 56.2 हो गया.

स्क्रैप सेंटरों की कार्यप्रणाली पर कसेगा शिकंजा

- प्रदूषण रोकने उपकरणों के मानक तय करेगी सरकार
- पंजीकृत केंद्रों को आधुनिक मशीनें लगाना अनिवार्य



नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 नवंबर. देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार वाहन स्क्रैप नीति को और सख्त बनाने जा रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए स्क्रैप केंद्रों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के मानक तय कर रहा है.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत देशभर के सभी पंजीकृत वाहन स्क्रैप केंद्रों को एक जैसे और आधुनिक उपकरण रखने होंगे. सरकार की योजना इसी साल नए नियमों की अधिसूचना जारी करने की है. इनके अगले साल से लागू होने की संभावना है. अभी देश में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों का कोई एक समान मानक नहीं है. अलग-अलग केंद्र अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. इससे स्क्रैपिंग की प्रक्रिया में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना मुश्किल होता है. नए नियम लागू होने के बाद केंद्रों को निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करना होगा. इससे मनमाने तरीके से वाहनों की स्क्रैपिंग पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

1.94 लाख वाहन स्क्रैप किए जा चुके है

आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से वाहनों को व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग हिस्सों में तोड़ने और उपयोगी सामग्री को अलग करने की प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी. हालांकि, नए नियमों में उपकरणों के तकनीकी मानक और केंद्रों के लिए विस्तृत शर्तें अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी. वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक देश के पंजीकृत स्क्रैप केंद्रों पर 1.94 लाख वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं. सरकार का उद्देश्य स्क्रैपिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के अभियान को गति मिल सके.

अमूल ने घी-बटर महंगा किया

- 1 किलो घी 50 बढ़कर 680 का हुआ
- नकली घी पर कार्रवाई के बाद मांग बढ़ी



नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 नवंबर. त्योहारी सीजन में डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच अमूल ने घी और बटर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने अलग-अलग पैक पर 3 से 50 रुपए तक दाम बढ़ाए हैं. एक किलो घी का कार्टन अब 630 रुपए के बजाय 680 रुपए में मिलेगा.

वहीं 500 ग्राम प्योर घी का पाउच 325 से बढ़कर 345 रुपए का हो गया है. बटर के 100 ग्राम पैक पर 3 रुपए और 500 ग्राम पैक पर 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. नई कीमतों के अनुसार अमूल के 100 ग्राम बटर पैक की कीमत 63 से बढ़कर 66 रुपए और 500 ग्राम पैक की कीमत 310 से बढ़कर 325 रुपए हो गई है. वहीं एक किलो घी के कार्टन पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. इससे नियमित रूप से घी और बटर खरीदने वाले परिवारों का मासिक खर्च बढ़ेगा. गुजरात और राजस्थान में नकली घी के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद ब्रांडेड घी की मांग में तेजी आई है. पिछले छह महीनों में दोनों राज्यों के अलग-अलग इलाकों से करीब दो लाख किलो नकली घी जब्त किया गया.

एलटीसीजी टैक्स घटाने से लौटेंगे विदेशी निवेशक

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 नवंबर. भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. हाल ही में बाजार नियामक सेबी ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को हटाने या इसमें भारी रियायत देने की सिफारिश की है. वर्तमान नियमों के तहत, देश में सूचीबद्ध शेयरों पर 20 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और 12.5 फीसदी एलटीसीजी टैक्स के अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी वसूला जाता है. सेबी की इस सिफारिश के बाद अब फरवरी में आने वाले आम बजट पर निवेशकों की निगाहें टिक गई हैं. विदेशी निवेशकों के सामने केवल टैक्स का ही नहीं, बल्कि 'फैंटम गेन्स' जैसी अन्य तकनीकी परेशानियां भी हैं.

एनएसई का मुनाफा हुआ 2578 करोड़ रुपये

- सरकारी खजाने में छह महीने में जमा किए 41,234 करोड़
- कुल आय 9% बढ़कर 4554 करोड़ रुपये पर पहुंची

नवभारत कनेक्ट

मुंबई, 3 नवंबर. देश के शेयर बाजार में बढ़ते कारोबार और निवेशकों की सक्रियता ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की कमाई को नई ऊंचाई दी है. वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में एनएसई का समेकित शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 2,578 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

पिछले साल की समान अवधि की तुलना में एक्सचेंज की कुल आय में भी 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4,554 करोड़ रुपये रही. वहीं परिचालन स्तर पर प्रदर्शन और मजबूत रहा. कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा 107 प्रतिशत बढ़कर 3,079 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन 76 प्रतिशत दर्ज किया गया.

एनएसई के कारोबार में सबसे अहम बढ़ोतरी कैश मार्केट में देखने को मिली. दूसरी तिमाही में यहां औसत दैनिक कारोबार 24 प्रतिशत बढ़कर 1,18,377 करोड़ रुपये हो गया. इक्विटी ऑप्शंस में औसत दैनिक कारोबार 47,977 करोड़ रुपये और इक्विटी फ्यूचर्स में 1,24,574 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. लेन-देन शुल्क से एक्सचेंज को 3,035 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो पिछले साल की समान तिमाही से 9 प्रतिशत अधिक है. एनएसई की कमाई के साथ सरकारी खजाने में उसका योगदान भी बड़ा रहा.

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में एक्सचेंज के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों को कुल 41,234 करोड़ रुपये का योगदान मिला. इसमें प्रतिभूति एवं कमोडिटी लेन-देन कर के 34,788 करोड़ रुपये, आयकर के 2,885 करोड़ रुपये और स्टाम्प ड्यूटी के 1,926 करोड़ रुपये शामिल हैं. पहली छमाही में एनएसई की समेकित कुल आय 9,807 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 5,698 करोड़ रुपये रहा. हालांकि दूसरी तिमाही में कुल व्यय 51 प्रतिशत घटकर 1,161 करोड़ रुपये रह गया. पिछले साल सेटलमेंट प्रावधान के रूप में 1,297 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च दर्ज होने के कारण इस बार व्यय में बड़ी गिरावट दिखाई दी. एनएसई के एमडी एवं सीईओ आशीषकुमार चौहान ने कहा कि दूसरी तिमाही एक्सचेंज के लिए महत्वपूर्ण रही.

AI+ स्मार्टफोन खरीदने का है आखिरी मौका

- दीपावली बाद 15 नवंबर से बढ़ेंगे दाम
- चुनिंदा मॉडल्स पर 3,000 रुपये तक की होगी बढ़ोतरी



नवभारत कनेक्ट

जयपुर, 4 नवंबर। स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. एआई+ स्मार्टफोन ने अपने पोर्टफोलियो के चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. नई कीमतें 15 नवंबर से लागू होंगी.

इसके बाद ग्राहकों को कुछ स्मार्टफोन खरीदने के लिए मौजूदा कीमतों की तुलना में 1,000 से 3,000 रुपये तक अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, ग्राहक 14 नवंबर तक इन फोन को पुरानी कीमतों पर खरीद सकेंगे. कंपनी के नए फैसले का असर एआई+ पल्स और नोवा सीरीज के चुनिंदा वैरिएंट्स पर पड़ेगा. कीमतों में बदलाव की सूची में एआई+ पल्स 2 एफई, पल्स 2, नोवा 2 5जी, नोवा 2 नियो 5जी, नोवा 2 पावर 5जी, नोवा 2 प्रो 5जी और नोवा 2 अल्ट्रा 5जी शामिल हैं. इन मॉडल्स के अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों में 1,000 से 3,000 रुपये तक का इजाफा किया जाएगा.

आरईसी के गुरुग्राम ऑफिस को पर्यावरण का सर्वोच्च सम्मान

5-स्टार गृहा रेटिंग से नवाजा, ऊर्जा बचत और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन में पेश की मिसाल

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 4 नवंबर 2026. पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास की दिशा में आरईसी लिमिटेड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के गुरुग्राम स्थित कार्यालय भवन को सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिस में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च 5-स्टार गृहा रेटिंग प्रदान की गई है. यह सम्मान भवन के टिकाऊ डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और संचालन एवं रखरखाव की प्रभावी कार्यप्रणाली को मान्यता देता है. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 18वें गृहा शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया. आरईसी की ओर से कार्यकारी निदेशक भूपेश चंदोलिया ने विभागाध्यक्ष एल. बी. नौटियाल और एस्टेट डिवीजन के अन्य सदस्यों के साथ यह सम्मान ग्रहण किया.



समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के सचिव और एमपीबीडीसी के प्रबंध निदेशक सिबी चक्रवर्ती एम. टेरी की महानिदेशक एवं गृहा काउंसिल की अध्यक्ष डॉ. विभा धवन, गृहा काउंसिल के उपाध्यक्ष एवं सीईओ संजय सेठ सहित कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे. 5-स्टार गृहा रेटिंग मिलना आरईसी के उन प्रयासों की पहचान है, जिनके तहत कंपनी अपने बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है.

कैनवा 1271 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 नवंबर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल ने टेक कंपनियों के कामकाज का तरीका बदलना शुरू कर दिया है. इसका असर अब नौकरियों पर भी दिखने लगा है.

ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन डिजाइन और पब्लिशिंग कंपनी कैनवा ने अपने कार्यबल में 22 प्रतिशत से अधिक कटौती और बड़े संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की है. इस फैसले से कम से कम 1,271 कर्मचारी प्रभावित होंगे.

घर और कार का लोन लेना हुआ सस्ता

- बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोसेसिंग शुल्क पर दी 100% छूट
- छह महीने तक लोन की प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह माफ

नवभारत कनेक्ट

मुंबई, 2 नवंबर. घर और कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने विशेष पेशकश शुरू की है. बैंक पात्र होम लोन और चारपहिया वाहन लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देगा. यह सुविधा 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी.

बैंक के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य कर्ज लेने की शुरुआती लागत कम करना और रिटेल लोन कारोबार को बढ़ावा देना है.

बैंक की इस पेशकश का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत ग्राहकों का सिबिल पर्सनल क्रेडिट स्कोर 725 या उससे अधिक होना चाहिए. होम लोन की विभिन्न योजनाओं में यह छूट मिलेगी. इसमें टॉप-अप होम लोन, स्मार्ट होम लोन और स्टार डायमंड होम लोन शामिल हैं. बैंक की निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले ग्राहक होम लोन टेकओवर यानी दूसरे बैंक से अपना मौजूदा होम लोन ट्रांसफर कराने पर भी इसका लाभ ले सकेंगे.

यह छूट केवल पात्र लोन पर लागू प्रोसेसिंग शुल्क के लिए है. इसे ब्याज दर में छूट या अन्य सभी बैंकिंग शुल्कों की माफी नहीं समझना चाहिए. लोन की मंजूरी, ब्याज दर, अन्य शुल्क और अंतिम पात्रता बैंक के नियमों के अनुसार तय होंगे. ग्राहक आवेदन से पहले अपनी नजदीकी शाखा या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

समाचार विशेष

अडानी पावर कंपनी ने दिया बीएचईएल को बड़ा तोहफा

- 6,400 मेगावाट की चार परियोजनाओं का ऑर्डर मिला
- चार ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए बॉयलर

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 4 नवंबर 2026. देश के बिजली उत्पादन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को बड़ी कामयाबी मिली है. कंपनी ने अडानी पावर लिमिटेड से देशभर में चार ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए बड़े घरेलू अनुबंध हासिल किए हैं.

इन परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 6,400 मेगावाट होगी. इस ऑर्डर के तहत बीएचईएल महत्वपूर्ण विद्युत उपकरणों की आपूर्ति के साथ निर्धारित सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी. चारों ताप विद्युत परियोजनाओं में प्रत्येक की क्षमता 2×800 मेगावाट निर्धारित की गई है. यानी हर परियोजना में 800 मेगावाट की दो उत्पादन इकाइयां स्थापित होंगी. बीएचईएल इन परियोजनाओं के लिए बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर और जरूरी सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगी. अनुबंधों का क्रियान्वयन अडानी पावर की परियोजना संबंधी जरूरतों और निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा.

देश की कुल उपयोगिता स्तर की पारंपरिक बिजली उत्पादन क्षमता में कंपनी का योगदान 53 प्रतिशत है. अडानी पावर से मिले ये चारों अनुबंध बीएचईएल की तकनीकी विशेषज्ञता और बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की क्षमता में ग्राहक के भरोसे को दर्शाते हैं. इन परियोजनाओं के जरिए देश की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार में मदद मिलेगी.

विद्युत उपकरण निर्माण में मजबूत पहचान

बीएचईएल देश और विदेश में बिजली उत्पादन उपकरणों की स्थापना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. कंपनी के मुताबिक, दुनिया भर में उसके 214 गीगावाट से अधिक क्षमता के विद्युत उत्पादन उपकरण स्थापित हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत में उपयोगिता स्तर की ताप विद्युत क्षमता में उसकी हिस्सेदारी 54 प्रतिशत रही. वहीं, परमाणु ऊर्जा के द्वितीयक पक्ष में 60 प्रतिशत और जल विद्युत क्षेत्र में 43 प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज की गई.

एनबीसीसी ने जोड़े कर्मचारी और विद्यार्थी

सतर्कता सप्ताह में शपथ से लेकर रील प्रतियोगिता तक आयोजित

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 4 नवंबर. सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एनबीसीसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए. इनमें कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों और विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी की. सप्ताह की शुरुआत 26 अक्टूबर को एनबीसीसी के निगमित कार्यालय में सत्यनिष्ठा की शपथ के साथ हुई. इस अवसर पर निदेशक (वाणिज्य) डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वित्त) अंजीव कुमार जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी ऋतु पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मचारियों को ईमानदारी एवं नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई.



प्रतियोगिताओं से जोड़ा परिवार और विद्यार्थी

सप्ताह के दौरान आशुभाषण, स्लोगन लेखन, चित्रकला, पेंटिंग और रील निर्माण प्रतियोगिताएं कराई गईं. वहीं, परियोजना स्थलों पर कर्मचारियों के बच्चों और विद्यार्थियों के लिए चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं. इन गतिविधियों के माध्यम से एनबीसीसी ने नैतिक मूल्यों और ईमानदार कार्यसंस्कृति का संदेश व्यापक समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया. समापन पर संगठन ने अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई.

ब्रजभूषण ने भाजपा को झुकाया

नई दिल्ली, 4 नवंबर. भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा की टिकट नहीं दी थी. हरियाणा की महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण को लेकर हुए विवाद की वजह से उनकी टिकट कट गई थी. उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिली और वे जीत भी गए.

हालांकि उसके बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की भाजपा से नाराजगी कम नहीं हुई. उन्होंने अयोध्या में राममंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में खुल कर कहा कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं और वे नाम लेंगे तो विवाद हो जाएगा. इसके बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय भी तेवर दिखाया, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि भाजपा को उनके सामने झुक कर समझौता करना पड़ा है. असल में राज्यसभा चुनाव के समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसे संकेत दिए कि वे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं. अपने विधायकों की संख्या के लिहाज से सपा दो सीटें जीतने की स्थिति में थी. उन दो सीटों पर रामगोपाल यादव और रिलंयास समूह से जुड़े धनराज नथवानी को टिकट दे दी गई.



विशेष | भाजपा का विशेष अभियान; 24 विभागों को मिला जिम्मा

विपक्ष को घेरने के लिए सड़क पर उतरने की रणनीति

लखनऊ, 4 नवंबर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंच बढ़ाने और विपक्ष के नकारात्मक प्रचार का जवाब देने के लिए अपने 24 प्रकोष्ठों को सक्रिय कर दिया है. शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यापारी, युवा, मजदूर और रेहड़ी-पटरी कारोबारियों समेत विभिन्न वर्गों के बीच संपर्क और संवाद बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रकोष्ठों को सौंपी गई है. साथ ही एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष को तथ्यात्मक जवाब देने वाले लोगों को तैयार करने की रणनीति बनाई गई है.

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रकोष्ठ संकुल की प्रदेश बैठक में राष्ट्रीय समन्वयक वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों को चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी सर्वव्यापी भाजपा को सर्वस्पर्शी बनाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारों की योजनाओं और फैसलों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाकर उन्हें संगठन से जोड़ना होगा. लगातार संपर्क के जरिये पार्टी के पक्ष में जनसमर्थन तैयार करना होगा. प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पदाधिकारी केवल प्रकोष्ठ संयोजक की भूमिका तक सीमित न रहें, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय भागीदारी निभाएं.

पदयात्राओं से विपक्ष को घेरेगी पार्टी

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से घेरने के लिए सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई है. पार्टी लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं निकालकर विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी. इस अभियान का आगाज मंगलवार को राजधानी और बरेली से किया गया. पांच नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी. इस दौरान विपक्ष की देश विरोधी राजनीति, सत्ता परिवर्तन के खतरनाक एजेंडे को जनता के सामने रखा जाएगा.

उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भागीदारी बढ़ाने और युवाओं, महिलाओं समेत सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि संपर्क, संवाद और समन्वय से समाज के सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ना है. संगठन की जिम्मेदारी पूरी क्षमता, परिश्रम और समर्पण से निभाएं, ताकि चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत में योगदान दे सकें.